



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासने द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, ११ मार्च, १९९६/२१ फाल्गुन, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-४, ११ मार्च, १९९६

संख्या १-३१/९६-वि० ल०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन निमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, १९९६

(1996 का विधेयक संख्यांक 20) जो दिनांक 11 मार्च, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

के० एल० वर्मा,  
सचिव।

1996 का विधेयक संख्यांक 20

## उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1996 है।

1971 का 5

2. उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में "एक हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे। धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3-क में, "नौ सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार चार सौ" शब्द रखे जाएंगे। धारा 3-क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क में, "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "साठ हजार" शब्द रखे जाएंगे। धारा 6-क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में, "एक हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार" शब्द रखे जाएंगे। धारा 9 का संशोधन।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन खर्चों, जो कि माननीय उप-मन्त्री को जन-प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उत्पन्न करने पड़ते हैं, में तेज वृद्धि के कारण उप-मन्त्री को संदेय वेतन को एक हजार पांच सौ रुपये से दो हजार पांच सौ रुपये और सत्कार भत्ता को नौ सौ रुपये से एक हजार चार सौ रुपये तक बढ़ाना तथा उसके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थान या उसके स्थायी निवास स्थान पर संस्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों पर व्यय की प्रतिपूर्ति को एक हजार पांच सौ से तीन हजार रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाना और रेलवे या वायुमार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा की अधिकतम सीमा किसी वित्तीय वर्ष में चालीस हजार किलोमीटर से साठ हजार किलोमीटर तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। अतः उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,  
मुख्य मन्त्री।

गिमला:

11 मार्च, 1996

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 5 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से अतिरिक्त आवर्ती खर्च होगा। वर्तमानतः उप-मन्त्री का कोई पद नहीं है, अतः अन्तर्बिलित वार्षिक खर्च का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या जी० ए० डी० सी० (पी० ए०) 4-23/94]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1996 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 20 of 1996.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF DEPUTY MINISTERS  
(HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Salaries and Allowances of Deputy Ministers  
(Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971).*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in  
the Forty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Deputy  
Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 1996.

Short title.

5 of 1971

2. In section 3 of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers  
(Himachal Pradesh) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), for  
the words “one thousand and five hundred”, the words “two thousand  
and five hundred” shall be substituted.

Amendment  
of section 3.

3. In section 3-A of the principal Act, for the words “nine  
hundred”, the words “one thousand and four hundred” shall be  
substituted.

Amend-  
ment of  
section 3-A.

4. In section 6-A of the principal Act, for the words “forty thousand”,  
wherever these occur, the words “sixty thousand”, shall be substituted.

Amend-  
ment of  
section 6-A.

5. In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), in first  
proviso, for the words “one thousand and five hundred”, the words  
“three thousand” shall be substituted.

Amend-  
ment of  
section 9.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which an Hon'ble Deputy Minister, as a public representative, had to incur on account of various demands of public life, it has been considered necessary to increase the salary from Rs. 1500/- to Rs. 2500/- and sumptuary allowances from Rs. 900/- to Rs. 1400/- payable to a Deputy Minister and to increase the re-imbursement of telephone charges from Rs. 1500/- to Rs. 3000/- per month to meet the expenses of local and outside calls in respect of telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence and to raise the maximum limit of free transit by railway or by air facility from forty thousand kilometres to sixty thousand kilometres in a financial year. This has necessitated the amendments in the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SHIMLA :  
The 11th March, 1996.

VIRBHADRA SINGH,  
Chief Minister.

## FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 5 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer. At present there is no office of Deputy Minister, as such the annual expenditure involved can not be anticipated.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C (PA)-4-23/94]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 1996, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.